

शब्दावली

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)	<p>संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा जाता है। प्राप्ति और संवितरण को तीन भागों के अंतर्गत दिखाया जाता है जिसमें सरकारी खाते रखे जाते हैं, अर्थात् (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि, और (iii) लोक लेखा।</p>
बजट एक नजर में	<p>यह दस्तावेज़ केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को हस्तांतरित कर राजस्व, अन्य प्राप्तियों और संसाधनों के विवरण के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरण में संक्षेप में दिखाता है। यह दस्तावेज़ सरकार के घाटे को भी दर्शाता है।</p>
पूंजीगत व्यय	<p>एक पूंजीगत प्रकृति के व्यय को व्यापक रूप से एक भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस संपत्ति बढ़ाने या आवर्ती देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है।</p>
पूंजीगत प्राप्ति	<p>पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार और विदेशी सरकारों/संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल होते हैं। इसमें सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली और सरकारी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय भी शामिल है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त राशि भी शामिल है।</p>
भारत की संचित निधि	<p>भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल, आंतरिक और बाहरी ऋणजारी करके, सभी संचित ऋण और ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन, संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित "भारत की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि का निर्माण करेंगे।</p>
प्रभावी राजस्व घाटा	<p>प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय (राजस्व खाते पर) और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर के रूप में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए कम अनुदान के रूप में समझा जा सकता है जिसे राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।</p>

विदेशी कर्ज	सरकार द्वारा विदेशी सरकारों और विदेशों में वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण, ज्यादातर विदेशी मुद्रा में।
वित्त लेखा	वित्त लेखे राजस्व और पूंजी खातों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों के खातों को प्रस्तुत करते हैं, सार्वजनिक ऋण के खातों और देनदारियों और परिसंपत्तियों के रूप में खातों में दर्ज शेष राशि।
वित्त विधेयक	अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का विवरण देते हुए संविधान के अनुच्छेद 110(1)(ए) के तहत आवश्यकता की पूर्ति में प्रस्तुत किया गया धन विधेयक है। एक बार जब वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाता है, तो यह वित्त अधिनियम बन जाता है।
राजकोषीय घाटा	एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ऋण प्राप्तियों को छोड़कर, निधि में कुल प्राप्तियों पर ऋण की अदायगी को छोड़कर, भारत की संचित निधि से कुल अधिक संवितरण।
राजकोषीय नीति	सरकार की राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी राजस्व में वृद्धि और सरकारी व्यय से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय और संसाधन प्रबंधन जिम्मेदारियों का कितनी अच्छी तरह निर्वहन किया गया है।
सकल घरेलू उत्पाद	सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) विशिष्ट अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसकी गणना आमतौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है। इसमें सभी निजी और सार्वजनिक उपभोग, सरकार के परिव्यय, निवेश और निर्यात कम आयात शामिल हैं जो एक परिभाषित क्षेत्र के भीतर होते हैं। जी डी पी को निर्दिष्ट आधार वर्ष के संदर्भ में स्थिर कीमतों पर और वर्तमान कीमतों पर भी काम किया जाता है (जिसमें मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में बदलाव या समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि शामिल है)।

गारंटियां	संविधान का अनुच्छेद 292 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, गारंटी देने के लिए करता है, जैसा कि संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत में उठाए गए ऋण शामिल हैं। यह भारत की संचित निधि में जुटाए गए और जमा किए गए ऋणों तक ही सीमित है।
ऋण और अग्रिम	इसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, विदेशी सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।
सार्वजनिक खाता	भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त संचित निधि में जमा किए गए धन के अलावा अन्य सभी सार्वजनिक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाता है। ये वे धन हैं जिनके संबंध में सरकार बैंकर के रूप में अधिक कार्य करती है।
सार्वजनिक ऋण	भारत की संचित निधि में अनुबंधित आंतरिक और बाहरी स्रोतों से सरकारी ऋण को सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है।
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता।
राजस्व व्यय	रखरखाव, मरम्मत, रखरखाव और काम करने के खर्च पर शुल्क, जो एक चालू क्रम में संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन चलने के लिए किए गए अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदान को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही कुछ अनुदान पूंजीगत परिसंपत्ति बनाने के लिए हो।
राजस्व प्राप्तियां	इनमें सरकार द्वारा लगाए गए करों और शुल्कों की आय, सरकार द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
अर्ध-राजकोषीय संचालन	ये सामान्य सरकारी इकाइयों के अलावा अन्य संस्थागत इकाइयों द्वारा किए गए सरकारी संचालन हैं। इन परिचालनों का अर्थव्यवस्था पर सरकारी इकाइयों के समान ही राजकोषीय नीति प्रभाव पड़ता है।